ber of 282 projects at a total cost of Rs. 113.05 lakhs. Six departmental projects involving a total grant of Rs. 60.00 lakhs were also approved. The total number of minor research projects approved during 1976-77 was 1021, at a total cost of Rs. 35.20 lakhs. In the fields of Humanities and Social Sciences, 29 advanced research projects were approved and a grant of Rs. 6.90 lakhs was committed in addition to 212 short-term projects involving a grant of Rs. 5.37 lakhs. During 1976-77, the Commission has invited three University Departments for participation in the programme of Special Assistance to Departments in the Humanities and Social Sciences. During 1976-77, the Commission also awarded 1191 Associateships/Fellowships for research programmes in various subjects.

Utilisation of surplus waters of Indian Rivers

38. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA:

SHRI HARGOVIND VERMA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the quantity of waters of Indian rivers that goes waste in the ocean; and

(b) the scheme to utilize the water for agriculture and drinking purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Out of a total estimated annual flow of 1,850,000 M. Cu. M. (1500 M. A. Ft.) of Indian rivers it is assessed that as at present 1,480, 000 M. Cum. (1200 M. A. Ft.) goes to the sea.

(b) Irrigation and drinking water supply are State subjects and the responsibility for planning, investigation, formulation of projects and their implementation and operation and maintenance vests with the State Governments. A large number of schemes have already been taken up and more are being planned for utilisation of these waters for agriculture and other beneficial purposes.

जाति प्रथा समाप्त करने पर स्कूलों में पाठ्यक्रम

39. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे" सम्बन्धी लेखों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : (क) और (ख) . राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित 'दस वर्षीय स्कूल के लिए ढांचा' में इस बात का समर्थन किया गया है कि लिंग, जात-पात, धर्म, भाषा अथवा प्रदेश पर आधारित किसी भी किस्म के भेदभाव से घृणा करनी चाहिए, क्योंकि यह आधुनिक भारत के विकास के लिए अविवेकी, अस्वभाविक एवं हानिप्रद होगा और यह कि सभी विषयों को ऐसे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे छात्रों में वैज्ञानिक मानवतावाद की भावना विकसित हो सके । सामाजिक विज्ञान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातन्त्र के मूल्यों एवं आदर्शों को प्रोन्नत करती है । इन पुस्तकों में छात्रों में इस सूझ-बूझ को विकसित करने का प्रयास किया गया है कि जाति प्रथा समाज क विभाजित करती है और इसलिए सामाजिक समानता लानें तथा देश की प्रगति में दलित वर्गों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए, हमें